



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

12 AUG 1970

सं. 31]

नई विल्सी, शनिवार, अगस्त 1, 1970 (आषाढ 10, 1892)

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1970 (SRAVANA 10, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न हो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 23 जून 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 23rd June 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4
		— NIL —	

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और मंकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 633	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 3137
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लिफ्टिंगों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	885	भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	481
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और मंकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	61	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	847
भाग I—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लिफ्टिंगों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	935	भाग III—खंड 2—एव.स्व.कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	293
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें विधिमूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	491
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2511	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें पूरक संख्या 31— 25 जुलाई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	131 1287
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633	4 जुलाई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के द्वीपांत भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1298
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	885	PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3137
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	61	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	491
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	935	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	847
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	293
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2511	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	491
		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	131
		SUPPLEMENT NO. 31 Weekly Epidemiological Reports for week ending 25th July 1970	1287
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 4th July 1970	1298

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विवितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं।

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1970

सं० ३७-प्र०/७०—आज तक संशोधित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० ११-प्र०/६८, दिनांक २८ करवारी, १९६८ में प्रकाशित पूर्वता सारणी में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित मंशोधन आम सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :

(क) अम संख्या 16 के अन्त में—

“मेघालय का मुख्य मंत्री”
“राज्यों के उप-मुख्य मंत्री” जोड़े।

(ख) अम संख्या 21 के अन्त में—

“मेघालय विधान सभा का अध्यक्ष” जोड़े।

(ग) अम संख्या 22 में—

“(राज्यों के मंत्रिमण्डल के मंत्री” की प्रविष्टि के बाद “मेघालय के मंत्रिमण्डल के मंत्री” जोड़े।

(घ) अम संख्या 25 में—

(i) “(राज्यों के राज्य मंत्री” प्रविष्टि के बाद “मेघालय के राज्य मंत्री” जोड़े।
(ii) “राज्य की विधान सभाओं के उप-सभापति और उपाध्यक्ष” की प्रविष्टि के बाद “मेघालय विधान सभा का उपाध्यक्ष” जोड़े।

(ङ) अम संख्या 26 में—

“राज्यों के उप मंत्री” की प्रविष्टि के बाद “मेघालय के उप मंत्री” जोड़े।

(छ) अम संख्या 30 के अन्त में—

“मेघालय सरकार का मुख्य सचिव”,
“राज्यों के महाधिवक्ता” जोड़े।

(ज) अम संख्या 31 के अन्त में—

“रेलों के महा प्रबंधक” जोड़े।

(झ) अम संख्या 32 में—

“रेलों के महा प्रबंधक” प्रविष्टि को हटा दें।

(ट) पाद-टिप्पणियों में—

“नोट १३ :—मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष, मेघालय मंत्रिमण्डल के सदस्य, मेघालय के राज्य मंत्री, मेघालय विधान सभा का उपाध्यक्ष, मेघालय के उप मंत्री और

मुख्य सचिव का स्थान असम के उच्च पदधारियों के तदमुहूर बाद में होगा” जोड़े।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-१, दिनांक ६ जुलाई 1970

संकल्प

सं० ८० एण्ड सी० II (6)/७०—प्राक्कलन समिति ने सीमा सङ्करण संगठन के ‘प्राक्कलन’ सम्बन्धी अपनी १२२वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि एक समिति नियुक्त की जाए और बेहतर यह होगा कि समिति योजना आयोग के तत्वावधान में नियुक्त की जाए जिसमें अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी हों। यह समिति उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमा धोरों में सीमा सङ्करण कार्यक्रम का सामाजिक अधिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करे और राज्य सरकारें सीमा धोरों के विकास की अपनी योजनाओं को किस प्रकार सीमा सङ्करण के कार्यक्रम के साथ समेकित कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में सिफारिशें करें। इस सिफारिश का अनुसरण करते हुए एक समिति गठित करने का निश्चय किया गया है जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :—

गठन

- श्री जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव, अध्यक्ष योजना आयोग।
- जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का सदस्य एक प्रतिनिधि।
- सीमा सङ्करण विकास बोर्ड का एक प्रति- सदस्य निधि।
- जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार का सदस्य एक प्रतिनिधि।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक प्रति- सदस्य निधि।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का एक सदस्य प्रतिनिधि।
- पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रति- सदस्य निधि।
- असम सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य

9. नागालैण्ड राज्य सरकार का एक प्रति- सदस्य
निधि ।
10. नेफा प्रशासन का एक प्रतिनिधि . सदस्य
11. श्री सत प्रकाश, संयुक्त निदेशक, सदस्य-सचिव
योजना आयोग ।

विचारार्थ विषय

1. उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सीमा सङ्क कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना ।
2. राज्य सरकारें सीमा क्षेत्रों के विकास की अपनी योजनाओं को किस प्रकार सीमा सङ्क निर्माण के कार्यक्रम के साथ समेकित कर सकती है इस सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । परन्तु समिति उन स्थानों का दौरा कर सकती है जिन्हें वह अपने कार्य के लिए आवश्यक समझे ।

आशा है कि राज्य सरकारें और अन्य सम्बद्ध समिति को हर प्रकार की सहायता देंगे जिसकी उसे आवश्यकता होगी और जो भी सूचना वह चाहे उसे उपलब्ध करेंगे ।

आवेदन

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए तथा यामान्य सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाए ।

ए० प्रसाद, अवर सचिव

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1970

संकल्प

सं० एफ० १८-१९/७०-ज० स्वा० ई०—निर्माण कार्यों में वृद्धि होने से तथा जल पूर्ति और मल निष्कामन सुविधाओं की व्यवस्था सम्बन्धी मांग में वृद्धि होने से दिल्ली में जल पूर्ति और मल निष्कामन की एक बृहद् योजना (मास्टर प्लान) तैयार करना आवश्यक हो गया है । इस कार्य के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का निश्चय किया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

1. सलाहकार (ज० स्वा० ई०), अध्यक्ष
केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्थान,
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण,
आवास एवं नगर विकास मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग) निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।
2. मुख्य अभियन्ता, सदस्य
केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग,
दिल्ली जीवन ।

3. मुख्य अभियन्ता, सदस्य
जल पूर्ति एवं मल निष्कामन उपक्रम,
दिल्ली नगर निगम ।
4. मुख्य अभियन्ता (सिविल), सदस्य
नई दिल्ली नगर पालिका ।
5. मुख्य अभियन्ता, सदस्य
दिल्ली विकास प्राधिकार ।
6. मंत्रिव, सदस्य
दिल्ली बाड़ समन्वय समिति,
गृह मंत्रालय ।
7. विशेष कार्य अधिकारी, सदस्य
तथा अधीक्षक अभियन्ता,
योजना एवं विकास सेल,
दिल्ली प्रशासन ।
8. उप-सलाहकार, सदस्य
केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी
संगठन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन,
निर्माण, आवास एवं नगर विकास
मंत्रालय ।
9. सहायक सलाहकार (ज० स्वा० ई०), सदस्य-सचिव
केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ।
2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—
- (क) बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए
दिल्ली की जल पूर्ति को बढ़ाने के
मोतों के बारे में सलाह देना;
- (घ) दिल्ली की जल पूर्ति-वितरण पद्धति,
आन्तरिक पद्धति, जलवाहक नल,
जलाशय आदि के लिए जन संख्या,
प्रति व्यक्ति सप्लाई, व्यस्तता के
कारण, बागबानी और औद्योगिक
अपेक्षाओं आदि को दृष्टि में रखते
हुए एक बृहद् योजना (मास्टर प्लान)
तैयार करना ;
- (ग) यह बतलाना कि नई दिल्ली नगर
पालिका और दिल्ली छावनी के क्षेत्रों
में जल पूर्ति को व्यापक पूर्ति के लिए
कहाँ तक पूर्णतः पृथक् किया जा
सकता है;
- (घ) दिल्ली के मल निष्कामन व्यवस्था
के लिए एक बृहद् योजना (मास्टर
प्लान) तैयार करना ;
और
- (ङ) ऐसे अन्य विषय जो उपर्युक्त कामों के
आनुपर्याप्ति हों ।
3. यह समिति यथावश्यक तथा ऐसे स्थानों पर जिन्हें
अध्यक्ष आवश्यक समझे अपनी बैठक आयोजित करेगी, समिति

ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहयोजित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

4. समिति छ: महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

निदेश दिया जाना है कि यह संकल्प भारत के गजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

अभियं भूपण मलिक, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 1970

सं० एफ० 11-1/67 सी० ए० I (I)—इस मंत्रालय की 30 जनवरी, 1970 की अधिसूचना सं० एफ० 11-1/67 सी० ए० I (I) के अन्म में, 30 सत्य प्रकाश के स्थान पर श्री गन्न चन्द्र अग्रवाल, निदेशक, पुरातत्व व संग्रहालय, जयपुर को गाजस्थान मरकार के एक प्रतिनिधि के स्वप्न में केन्द्रीय पुरातत्व मलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के स्वप्न में मनोनीत किया जाता है।

मरन सिंह, अवर सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 जुलाई 1970

संकल्प

सं० ई० प्र००-तीन-11/17/70—जम्मू और काश्मीर गज्य में सलाल पर, हिमाचल प्रदेश के मंदीर प्रदेश में बैंग मियून पर, और मणिपुर के संघीय प्रदेश में लोकतक पर भारत सरकार द्वारा हाथ में ली गई जल विद्युत परियोजनाओं के दक्षता-पूर्ण, मितव्ययी और शोध कार्यान्वयन को मुनिष्वित करने के विचार से भारत सरकार ने एक निदेशन समिति और 'केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड' स्थापित करने का निर्णय किया है।

2. निदेशन समिति का गठन और उसके कार्य :—

(1) निदेशन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

- (i) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री;
- (ii) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री;
- (iii) विद्युत मंत्री, जम्मू और काश्मीर/मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश / मुख्य मंत्री, मणिपुर।
- (iv) पंणा-3 में निर्दिष्ट केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष।

इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री और उनकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री करेंगे। उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे :

(2) समिति की बैठकें वर्ष में एक बार अथवा जब कभी उचित समझा गया तो इस से कम अन्तराल के साथ की जाएँगी।

(3) समिति स्वीकृत बजट प्रस्थानों और समय-समय पर स्वीकृत अनुमानों के अनुसार उपर्युक्त तीन जल-विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करेगी। समिति केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड को उन मामलों के सम्बन्ध में निदेश जारी करेगी जिन्हें समिति उचित समझेगी अथवा समिति को बोर्ड द्वारा जो निर्दिष्ट किए जाएँगे।

3. केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड का गठन और उसके कार्य :—

(1) इस बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

(i) सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यव विभाग-सिंचाई और विद्युत) अथवा उसका प्रतिनिधि	सदस्य
(iv) मुख्य सचिव, जम्मू और काश्मीर/मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश/मुख्य सचिव, मणिपुर	सदस्य
(v) निदेशक (विदेशी मुद्रा और विद्युत), सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	सदस्य
(vi) उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
(vii) सदस्य (जल-विद्युत), केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
(viii) सदस्य (अधिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
(ix) मुख्य अभियंता, सलाल/मुख्य अभियन्ता, लोकतक/उप-मुख्य अभियंता, सियुल	सदस्य
(x) केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड का वित्तीय सलाहकार	सदस्य

2. इस बोर्ड का कार्यालय नई दिल्ली में होगा। बोर्ड की सहायता के लिए एक पूर्ण-कालिक सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और आवश्यकतानुसार अन्य स्टाफ होगा। सचिव, वित्तीय सलाहकार और अन्य स्टाफ की नियुक्ति सिंचाई और विद्युत मंत्रालय करेगा।

(3) बोर्ड आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाएगा और अपनी बैठकों में उन अन्य अधिकारियों को आमंत्रित करेगा जिन्हें

वह आवश्यक समझेगा। आवश्यकतानुसार यह उप समितियां भी नियुक्त कर सकता है।

(4) केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड विशेष रूप से और उपर्युक्त उपबन्धों की सामान्यता के प्रतिकूल न जा कर निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (i) परियोजना के प्राक्कलनों की जांच पड़ताल करेगा, अपेक्षित संशोधन सुझाएगा और भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की सिफारिश करेगा;
- (ii) अभिकल्पों को पैयार करने के लिए तथा विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने के लिए सभी प्रस्तावों की जांच करके उन पर अपना निर्णय देगा;
- (iii) मुख्य इंजीनियर/उप-मुख्य इंजीनियर तथा परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों को परियोजना के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन के मामलों की समय-समय पर जांच करके इससे सम्बन्धित स्वीकृति देगा;
- (iv) परियोजना के ठोस और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों की जांच करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां उनके लिए विशिष्टियां और दर-अनुसूचियां तैयार करेगा;
- (v) उन सभी उप-प्राक्कलनों और ठेकों को अपनी स्वीकृति देगा जिनकी लागत मुख्य इंजीनियर/उप-मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति शक्ति से अधिक होगी;
- (vi) परियोजना के मुख्य इंजीनियर/उप-मुख्य इंजीनियर की शक्तियों से परे सभी ठेकों के कार्यों अथवा ठेकों की सप्लाई से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति देगा;
- (vii) अपने कार्य को करने के उद्देश्य से शक्ति प्रत्यायोजन और प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम बनाएगा;

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th July 1970

No. 37-Pres./70.—The following amendments approved by the President to the Table of Precedence published in Notification No. 11-Pres./68, dated the 28th February, 1968, as amended up to date, are published for general information :—

(a) In Article 16—

Add at the end "Chief Minister of Meghalaya"
"Deputy Chief Ministers of States".

(b) In Article 21—

Add at the end "Speaker of Legislative Assembly of Meghalaya".

(c) In Article 22—

Add "Cabinet Ministers in Meghalaya" after the entry
"Cabinet Ministers in States".

(viii) उपलब्ध घन, परियोजना के आर्थिक पक्ष और द्रुत परिणामों की वांछनीयता को दृष्टि में रखते हुए परियोजना के विभिन्न भागों के निर्माण का कार्य-क्रम निर्धारित करेगा;

(ix) मुख्य इंजीनियर/उप-मुख्य इंजीनियर और अन्य अधिकारियों से निर्धारित कार्य में वे प्रगति रिपोर्ट मंगाएगा जो कि इस कार्य और व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित करेगा, परियोजना के विभिन्न भागों की प्रगति का पुनरावलोकन करेगा, और यह बताएगा कि कार्य की गति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए; और

(x) परियोजना के अधिकारियों के सम्बन्ध में, जब आवश्यक होगा, उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उचित अनुशासनिक कार्यवाही का सुझाव देगा।

(5) यह बोर्ड एक स्थाई समिति का गठन कर सकता है और इसे वे कार्य सौंप सकता है और वे शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। स्थायी समिति नियन्त्रण बोर्ड की ओर से उन तकनीकी, वित्तीय और अन्य मामलों पर अपना फैसला देगी जो कि इसे बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित मामलों पर स्थायी समिति के फैसलों का संक्षिप्त विवरण बोर्ड को उसकी अगली बैठक में उसके सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। स्थायी समिति अपने कार्य नियम स्वयं बनाएगी।

आवेदन

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को जम्मू और काश्मीर की सरकार, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के संघीय, प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय के बिनेट सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र प्रकाशित कर दिया जाए।

वी० वी० चारि, सचिव

(d) In Article 25—

(i) Add "Ministers of State in Meghalaya" after the entry "Ministers of State in States".

(ii) Add "Deputy Speaker of Legislative Assembly of Meghalaya" after the entry "Deputy Chairman and Deputy Speakers of State Legislatures".

(e) In Article 26—

Add "Deputy Ministers in Meghalaya" after the entry "Deputy Ministers in States".

(f) In Article 30—

Add at the end "Chief Secretary to the Government of Meghalaya".
"Advocates General of States".

(g) In Article 31—

Add at the end 'General Managers of Railways'.

(h) In Article 32—

Delete the entry "General Managers of Railways".

(i) In foot-notes—

Add "Note 13.—The Speaker of Meghalaya Legislative Assembly, Cabinet Ministers, "Ministers of State in Meghalaya, Deputy Speaker of Meghalaya Legislative Assembly and Deputy Ministers of Meghalaya and the Chief Secretary Meghalaya will rank after the corresponding dignitaries of Assam".

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 6th July 1970

RESOLUTION

No. T&C/II(6)/70.—The Estimates Committee in their 122nd Report on the (Estimates) of Border Roads Organisation has suggested that a Committee may be appointed preferably under the aegis of the Planning Commission consisting, *inter alia*, of the representatives of the State Governments concerned to assess the impact of the border road programme on the socio-economic development of the northern and north-eastern border areas and to make recommendations as to the manner in which the State Governments could integrate their plans for development of border areas with the programme for the construction of border roads. In pursuance of this recommendation it has been decided to set up a Committee with the following composition and terms of reference :

*Composition**Chairman*

1. Shri G. C. Baveja, Joint Secretary, Planning Commission.

Members

2. A representative of the Ministry of Shipping & Transport.
3. A representative of the Border Roads Development Board.
4. A representative of the Government of Jammu & Kashmir.
5. A representative of the Government of Uttar Pradesh.
6. A representative of the Government of Himachal Pradesh.
7. A representative of the Government of West Bengal.
8. A representative of the Government of Assam.
9. A representative of the Government of Nagaland.
10. A representative of the NEFA Administration.

Member-Secretary

11. Shri Sat Parkash, Joint Director, Planning Commission.

Terms of Reference

- (1) To assess the impact of the Border Roads programme on the socio-economic development of the northern and north-eastern border areas.
- (2) To make recommendations as to the manner in which State Governments could integrate their plans for development of the border areas with the programme for the construction of border roads.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi, but it may visit such places as may be necessary in connection with its work.

It is hoped that the State Governments and others concerned will afford the Committee all the assistance it may require and supply it with such information as it may ask for.

ORDER

ORDERED that the copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

A. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT**(Department of Health)**

New Delhi, the 20th June 1970

RESOLUTION

No. F.16-19/70-PHE.—With the increase in building activities and increase in the demand for water supply and provision of sewerage facilities, it has become necessary to prepare a Master Plan for Delhi's Water Supply and Sewerage. For this purpose, the Government of India have decided to set up a Committee consisting of :—

Chairman

1. Adviser (PHE) Central Public Health Engineering Organisation, Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development, (Department of Health), Nirman Bhawan, New Delhi.

Members

2. Chief Engineer, Central Public Works Department, Delhi Zone.
3. Chief Engineer, Water Supply & Sewage Disposal Undertaking, Delhi Municipal Corporation.
4. Chief Engineer (Civil), New Delhi Municipal Committee.
5. Chief Engineer, Delhi Development Authority.
6. Secretary, Delhi Floods Coordination Committee, Ministry of Home Affairs.
7. Officer on Special Duty and Superintending Engineer, Planning and Development Cell, Delhi Administration.
8. Deputy Adviser, Central Public Health Engineering Organisation, Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development.

Member-Secretary

9. Assistant Adviser (PHE), Central Public Health Engineering Organisation.
2. The terms of reference of the Committee shall be—
 - (a) to advise on the sources for augmenting Delhi's water supply to meet the increasing demand;
 - (b) to prepare a Master Plan for Delhi's Water Supply—distribution system, internal system, conveying mains, reservoirs etc.—taking into account population, per capita supply, peaking factor, gardening and industrial requirements, etc.;
 - (c) to suggest the extent to which the water supply to the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Cantonment areas could be completely isolated for bulk supplies;
 - (d) to prepare a Master Plan for Delhi's Sewerage system; and
 - (e) such other matters as are incidental to the above.

3. The Committee will hold its meeting as and when necessary and at such places as the Chairman may consider necessary. The Committee may also co-opt such other persons as may be considered necessary.

4. The Committee will submit its report within a period of six months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. B. MALIK, Lt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 14th July 1970

RESOLUTION

No. EL-III-11.17/70.—With a view to ensuring efficient, economic and early implementation of the hydro-electric

projects taken up by the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power at Salal in the State of Jammu and Kashmir, Bairat Siul in the Union Territory of Himachal Pradesh and Loktak in the Union Territory of Manipur, the Government of India have decided to set up a Committee of Direction and the "Central Hydro-electric Projects Control Board".

2. Constitution and Functions of the Committee of Direction

(1) The Committee of Direction will consist of the following :

- (i) the Union Minister of Irrigation and Power;
- (ii) the Union Deputy Minister of Irrigation & Power;
- (iii) the State Minister for Power, Jammu & Kashmir/Chief Minister, Himachal Pradesh/Chief Minister, Manipur;
- (iv) the Chairman of the Central Hydro-electric Projects Control Board referred to in para (3).

The Committee will be presided over by the Union Minister of Irrigation and Power and, in his absence, by the Union Deputy Minister of Irrigation and Power. The Vice-Chairman, Central Water and Power Commission, will act as Secretary to the Committee.

(2) The meetings of the Committee shall be held once every year or at shorter intervals whenever considered necessary.

(3) The Committee will lay down the policy in regard to the execution of the three hydro-electric projects indicated above in accordance with the estimate as sanctioned from time to time and sanctioned budget provisions. The Committee will issue directions to the Central Hydro-electric Projects Control Board on such matters as it considers necessary or as may be referred to it by the Board.

3. Constitution and Functions of the Central Hydro-Electric Projects Control Board

(1) The Board will consist of the following :—

Chairman

(i) Secretary, Ministry of Irrigation and Power.

Members

- (ii) Chairman, Central Water & Power Commission.
- (iii) Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure-I&P) or his representative.
- (iv) Chief Secretary, Jammu & Kashmir/Chief Secretary, Himachal Pradesh/Chief Secretary, Manipur.
- (v) Director (HE&P) Ministry of Irrigation and Power.
- (vi) Vice-Chairman, Central Water & Power Commission.
- (vii) Member (HE), Central Water & Power Commission.
- (viii) Member (D&R), Central Water & Power Commission.
- (ix) Chief Engineer, Salal/Chief Engineer, Loktak/Deputy Chief Engineer, Siul.
- (x) Financial Adviser of the Central Hydro-electric Projects Control Board.

(2) The Board's office will be at New Delhi. The Board will be assisted by a whole-time Secretary, a Financial Adviser and such other staff as may be considered necessary. The Secretary, the Financial Adviser and other staff will be appointed by the Ministry of Irrigation and Power.

(3) The Board will hold meetings as and when necessary and may invite to its meetings such other officers as may be

considered necessary. It may also appoint Sub-Committees when necessary.

(4) In particular and without prejudice to the generality of the provisions above, the Central Hydro-electric Projects Control Board shall :—

- (i) scrutinise the estimates of the project, advise necessary modifications and recommend the estimate for administrative approval of the Government of India;
- (ii) examine and decide all proposals preparation of designs and for obtaining expert advice;
- (iii) examine and approve from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial as it may deem necessary for the efficient execution of the project to the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer and other officers concerned with the execution of the project;
- (iv) examine and where necessary lay down specifications and schedule of rates for various classes of work with a view to sound and efficient execution of the project;
- (v) approve all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer;
- (vi) approve all proposals for award of work or supplies on contract which are beyond the powers of the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer of the project;
- (vii) frame rules as to delegation of powers and procedure for the purpose of carrying out its business;
- (viii) decide the programme of construction of different parts of the project keeping in view the funds available, the economic of the project and the desirability of obtaining quick results;
- (ix) receive such progress reports as it may prescribe both as to works and expenditure in the prescribed form from the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer and other officers, review the progress of different units of the project and lay down steps to be taken to expedite the work; and
- (x) fix responsibility and recommend suitable disciplinary action when necessary in the case of officers of the project.

(5) The Board may constitute a Standing Committee and entrust it with such of its functions and delegate such of its powers as it may deem fit. The Standing Committee shall take decisions on behalf of the Control Board on such technical, financial and other matters as may be delegated to it by the Board. The summary of the decisions of the Standing Committee on matters delegated to it by the Board shall be put up for information of the Board at its following meeting. The Standing Committee will frame its rules of business.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of the State of Jammu and Kashmir, and Union Territories of Himachal Pradesh and Manipur, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretary, Secretary to the President, Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. V. CHARI, Secy.